Test Cloud

Daily करेंट अफेयर्स

14 अगस्त 2025

NATIONAL AFFAIRS

1. DPIIT ने 'ज़ेप्टो नोवा' और 'हीरो फॉर स्टार्टअप्स' पहल के माध्यम से विनिर्माण स्टार्टअप्स को समर्थन देने के लिए ज़ेप्टो और हीरो मोटोकॉर्प के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

12 अगस्त, 2025 को, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (MoCI) के अंतर्गत उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) ने विनिर्माण क्षेत्र में स्टार्टअप्स के लिए समर्थन को मज़बूत करने हेतु ज़ेप्टो प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में किरणकार्ट टेक्नोलॉजीज़ प्राइवेट लिमिटेड) और हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड (हीरो मोटोकॉर्प) के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। 'ज़ेप्टो नोवा इनोवेशन चैलेंज' और 'हीरो फॉर स्टार्टअप्स' एक्सेलरेटर प्रोग्राम सहित इन पहलों का उद्देश्य भारत के विनिर्माण क्षेत्र में शुरुआती चरण के स्टार्टअप्स को मार्गदर्शन, विस्तार और संसाधन प्रदान करना है।

• DPIIT के निदेशक डॉ. सुमीत जारंगल और ज़ेप्टो के सह-संस्थापक कैलाव्य वोहरा द्वारा हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन (MoU) छह महीने लंबे 'ज़ेप्टो नोवा' इनोवेशन चैलेंज की औपचारिक शुरुआत करता है। यह कार्यक्रम विनिर्माण क्षेत्र में स्टार्टअप्स की पहचान और मार्गदर्शन पर केंद्रित है, जिससे उन्हें ज़ेप्टो के मज़बूत वितरण नेटवर्क और डिजिटल बुनियादी ढाँचे का लाभ उठाकर प्रोटोटाइप से बाज़ार-तैयार समाधानों तक आगे बढ़ने में मदद मिलती है।

• यह चुनौती हार्डवेयर, इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT), पैकेजिंग और टिकाऊ विनिर्माण में तकनीक विकसित करने वाले स्टार्टअप्स पर केंद्रित है। यह विशेष रूप से टियर II और टियर III शहरों के महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों और स्टार्टअप्स का समर्थन करता है, जिससे विनिर्माण क्षेत्र में समावेशी विकास को बढ़ावा मिलता है। इस पहल के तहत, ज़ेप्टो 100 भारतीय स्टार्टअप्स को अपनी आपूर्ति श्रृंखला में एकीकृत करेगा, जिससे उन्हें सीधे बाज़ार में पहुँच मिलेगी और उनके नवाचारों को प्रदर्शित करने के लिए एक मंच मिलेगा।

• DPIIT ने नवाचार त्वरक कार्यक्रम 'हीरो फॉर स्टार्टअप्स' के माध्यम से शुरुआती चरण में स्टार्टअप्स को समर्थन और विस्तार देने के लिए हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड (हीरो मोटोकॉर्प) के साथ एक साझेदारी समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए। इस समझौता ज्ञापन पर DPIIT के निदेशक डॉ. सुमीत जारंगल और हीरो मोटोकॉर्प के ग्लोबल इनोवेशन पोर्टफोलियो लीड उत्कर्ष मिश्रा ने हस्ताक्षर किए, जो विनिर्माण क्षेत्र में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए एक रणनीतिक सहयोग को दर्शाता है।

Key Points:-

(i) यह सहयोग भविष्य की गतिशीलता, स्वच्छ प्रौद्योगिकी और गहन प्रौद्योगिकी में समाधान विकसित करने वाले स्टार्टअप्स पर केंद्रित होगा। चयनित स्टार्टअप्स को जर्मनी और भारत में हीरो मोटोकॉर्प की अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी) सुविधाओं, इसके व्यापक डीलर और आपूर्तिकर्ता नेटवर्क, और मार्गदर्शन तक पहुँच प्राप्त होगी, जिससे तेज़ी से विस्तार और औद्योगिक एकीकरण में मदद मिलेगी।

(ii) दोनों पहलों का उद्देश्य स्टार्टअप्स के लिए एक

संरचित सहायता प्रणाली प्रदान करना है। ज़ेप्टो नोवा विशेषज्ञों द्वारा संचालित कार्यशालाओं, मेंटरशिप सत्रों और क्षमता निर्माण के माध्यम से मार्गदर्शन प्रदान करता है, जबकि हीरो फॉर स्टार्टअप्स व्यावहारिक औद्योगिक मेंटरशिप, अनुसंधान एवं विकास तक पहुँच और अवधारणा के प्रमाण (PoCs) के पायलट अवसर प्रदान करता है। इन कार्यक्रमों का सामूहिक उद्देश्य भारत के विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र में नवाचार और व्यावसायीकरण के बीच की खाई को पाटना है।

(iii) इन समझौता ज्ञापनों के माध्यम से, स्टार्टअप्स को उत्पाद विकास में तेज़ी लाने, बाज़ार की जानकारी हासिल करने, और वित्तपोषण एवं उद्योग नेटवर्क तक पहुँच बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है। ज़ेप्टो नोवा और हीरो फॉर स्टार्टअप्स, दोनों ही स्टार्टअप्स को अपने नवाचारों का प्रदर्शन करने, औद्योगिक आपूर्ति श्रृंखलाओं में एकीकृत होने और भारत के विनिर्माण एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्रों के विकास में योगदान देने के लिए मंच प्रदान करते हैं, जिससे राष्ट्रीय स्तर पर एक मज़बूत स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा मिलता है।

2. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पंजाब, ओडिशा और आंध्र प्रदेश में ₹4,600 करोड़ के निवेश के साथ चार नई सेमीकंडक्टर इकाइयों को मंजूरी दी।

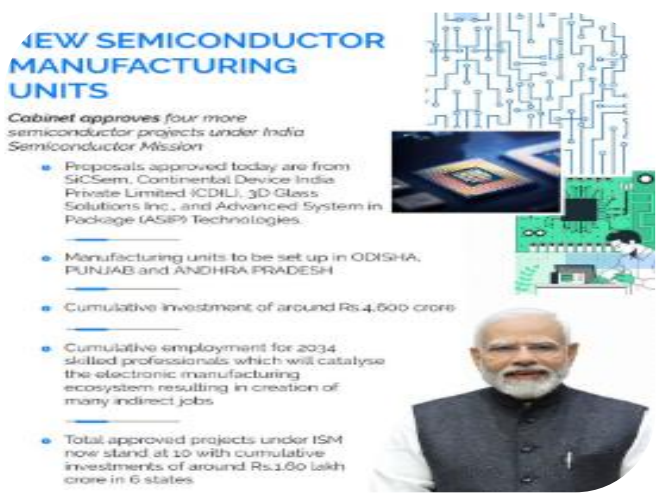

12 अगस्त, 2025 को, भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पंजाब, ओडिशा और आंध्र प्रदेश राज्यों में चार नई सेमीकंडक्टर निर्माण इकाइयों की स्थापना को मंज़ूरी दी। भारत सेमीकंडक्टर मिशन (ISM) के तहत यह रणनीतिक कदम लगभग ₹4,600 करोड़ के महत्वपूर्ण निवेश का प्रतिनिधित्व करता है और इसका उद्देश्य सेमीकंडक्टर उत्पादन में भारत की आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है।

- **स्वीकृत परियोजनाओं में ओडिशा में दो और आंध्र प्रदेश व पंजाब में एक-एक सेमीकंडक्टर इकाई शामिल है। इन सुविधाओं से 2,000 से ज़्यादा कुशल पेशेवरों के लिए रोज़गार सृजित होने और क्षेत्रीय आर्थिक विकास एवं तकनीकी उन्नति में योगदान मिलने की उम्मीद है।**

- **इनमें से एक परियोजना को अमेरिकी चिप निर्माता इंटेल और एयरोस्पेस एवं रक्षा कंपनी लॉकहीड मार्टिन सहित वैश्विक उद्योग जगत के दिग्गजों का समर्थन प्राप्त हुआ है। इन सहयोगों से भारत में उन्नत विनिर्माण तकनीकें और विशेषज्ञता आने की उम्मीद है, जिससे सेमीकंडक्टर उत्पादन में देश की क्षमताएँ बढ़ेंगी।**

- **इन इकाइयों की स्थापना भारत सेमीकंडक्टर मिशन के उद्देश्यों के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य भारत को सेमीकंडक्टर निर्माण और डिज़ाइन के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना है। ISM विदेशी सेमीकंडक्टर आयात पर निर्भरता कम करने और घरेलू उत्पादन क्षमताओं को बढ़ावा देने पर केंद्रित है।**

Key Points:-

(i) इन चार इकाइयों के जुड़ने से, भारत में स्वीकृत सेमीकंडक्टर परियोजनाओं की कुल संख्या दस हो गई है, जिनका संचयी निवेश लगभग ₹1.6 लाख करोड़ है। यह विस्तार एक मज़बूत सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने और महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक घटकों के लिए बाहरी स्रोतों पर निर्भरता

कम करने की भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

(ii) सरकार के सक्रिय दृष्टिकोण में सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए प्रोत्साहन प्रदान करना और अनुकूल वातावरण तैयार करना शामिल है। इसमें अनुसंधान एवं विकास, बुनियादी ढाँचे के विकास और कुशल कार्यबल के निर्माण के लिए उद्योग और शिक्षा जगत के बीच सहयोग को बढ़ावा देना शामिल है।

(iii) सेमीकंडक्टर निर्माण में भारत के रणनीतिक प्रयासों से वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स आपूर्ति श्रृंखला में उसकी स्थिति मज़बूत होने की उम्मीद है। महत्वपूर्ण निवेश और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों के साथ, भारत का लक्ष्य वैश्विक सेमीकंडक्टर बाज़ार में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में उभरना है, जिससे तकनीकी प्रगति, आर्थिक विकास और महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक घटकों में आत्मनिर्भरता में योगदान मिलेगा।

3. भारत और जाम्बिया ने द्विपक्षीय सहकारी व्यापार को बढ़ावा देने और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए व्यापार सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए।

12 अगस्त, 2025 को भारत सरकार (GoI) ने द्विपक्षीय व्यापार गठबंधनों को मजबूत करने और दोनों देशों के बीच सहकारी व्यापार पहल को बढ़ावा देने के लिए जाम्बिया गणराज्य के साथ घोषित व्यापार सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए।

• व्यापार सहयोग समझौते का उद्देश्य सहकारी व्यापार गठबंधनों को बढ़ावा देना और भारत तथा जाम्बिया की सहकारी संस्थाओं के बीच पारस्परिक रूप से लाभकारी साझेदारी को सुगम बनाना है। इसमें व्यापार सहयोग, ज्ञान साझाकरण और व्यावसायिक संबंधों के लिए एक ढाँचा तैयार करना शामिल है।

• भारत ने 18 जुलाई, 2025 को जाम्बिया के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए। एमओयू में सहकारी समितियों को बढ़ावा देने, व्यापार सुविधाओं को सक्षम करने और दीर्घकालिक आर्थिक विकास के लिए भारतीय और जाम्बियाई सहकारी क्षेत्रों के बीच सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया है।

• भारत सरकार का सहकारिता मंत्रालय (MoC) इस पहल का नेतृत्व कर रहा है और सहकारी निर्यात पारिस्थितिकी तंत्र को मज़बूत करने के लिए विदेशों में भारतीय मिशनों के साथ मिलकर काम कर रहा है। यह समझौता व्यापार गठबंधनों के लिए सुगठित समर्थन सुनिश्चित करता है और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों को बढ़ावा देता है।

Key Points:-

(i) राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड (NCEL) इस समझौते के अंतर्गत एक प्रमुख कार्यान्वयन निकाय है। एनसीईएल ने सेनेगल और इंडोनेशिया जैसे देशों, जिनमें सिंटन वैंटेज ट्रेडिंग (सेनेगल) और पीटी सिंटन सुरिनी नुसंतारा (इंडोनेशिया) शामिल हैं, के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करके अपनी वैश्विक पहुँच का विस्तार किया है, जिससे वैश्विक व्यापार सहयोग को बढ़ावा मिला है।

(ii) सहयोग समझौतों से वस्तुओं, सेवाओं और तकनीकी विशेषज्ञता के आदान-प्रदान में सुविधा होने की उम्मीद है। इन पहलों का उद्देश्य भारतीय सहकारी समितियों की वैश्विक उपस्थिति को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार साझेदारी को बढ़ाना और

ज़ाम्बिया के साथ भारत के आर्थिक संबंधों को मज़बूत करना है।

4. कर्नाटक ने 2029 तक 500 नए वैश्विक क्षमता केंद्र (GCCs) स्थापित करने के लिए "कैटालिस्ट" लॉन्च किया।

अगस्त 2025 में, बेंगलुरु टेक समिट से पहले, कर्नाटक सरकार ने KATALYST नामक एक समर्पित ईज़-ऑफ-डूइंग-बिज़नेस सेल की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य वैश्विक क्षमता केंद्रों (GCC) की स्थापना में तेज़ी लाना है। यह पहल राज्य की GCC नीति 2024-2029 का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसका लक्ष्य 2029 तक 500 नए GCC जोड़ना है।

• KATALYST एक एकल-खिड़की सुविधा प्रकोष्ठ के रूप में कार्य करता है जिसे GCCs के लिए अनुमोदन, मंज़ूरी और निवेशक सहायता को सुव्यवस्थित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस कार्यक्रम का शुभारंभ एक CEO ब्रेकफास्ट मीट के दौरान किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और 200 से अधिक उद्योग जगत के नेता शामिल हुए, जो कर्नाटक को एक वैश्विक GCCs केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक सक्रिय कदम है।

• GCC नीति 2024-2029 के तहत, कर्नाटक का लक्ष्य 2029 तक अपने मौजूदा GCC की संख्या को दोगुना करके लगभग 1,000 करना है। इस विस्तार से 3.5 लाख (350,000) नए रोज़गार सृजित होने, आर्थिक उत्पादन में 50 अरब अमेरिकी डॉलर का योगदान होने और भारत के GCCs बाज़ार में लगभग 50% हिस्सेदारी बनाए रखने की उम्मीद है। राज्य में वर्तमान में भारत के 30% से अधिक GCC स्थित हैं और देश के 35% GCC कार्यबल को रोजगार प्रदान करता है।

Key Points:-

(i) यह नीति बेंगलुरु और "बेंगलुरू से परे" दोनों क्लस्टरों पर केंद्रित है, जिसमें तीन वैश्विक नवाचार ज़िले स्थापित करने की योजना है—एक बेंगलुरु में और दो अन्य क्षेत्रों जैसे मैसूर, मंगलुरु, हुबली-धारवाड़, तुमकुरु, कलबुर्गी और शिवमोग्गा में। लचीले प्रोत्साहनों और शिथिल मानदंडों के माध्यम से 5-50 कर्मचारियों वाले छोटे "नैनो GCCs" को भी विशेष सहायता प्रदान की जाएगी।

(ii) GCCs को आकर्षित करने के लिए, राज्य बेंगलुरु के बाहर के केंद्रों के लिए ₹50 लाख तक के किराए की प्रतिपूर्ति, पाँच वर्षों के लिए बिजली शुल्क में छूट, इंटर्नशिप वजीफा प्रतिपूर्ति और अनुप्रयुक्त अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं के लिए वित्तपोषण जैसे लाभ प्रदान करता है। इस नीति में एक AI उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना, एक AI कौशल परिषद का गठन और उद्योग-अकादमिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए ₹100 करोड़ का नवाचार कोष शुरू करना भी शामिल है।

(iii) KATALYST के साथ, कर्नाटक का अनुमान है कि अगले पाँच वर्षों में GCC क्षेत्र 12-14% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ेगा। रणनीतिक प्रोत्साहनों, क्षेत्रीय विकास और अत्याधुनिक बुनियादी ढाँचे को मिलाकर, राज्य भारत के GCC परिदृश्य में अपने नेतृत्व को मज़बूत करना चाहता है और साथ ही पर्याप्त रोज़गार सृजन और नवाचार को बढ़ावा देना चाहता है।

5. BSF ने 11 से 17 अगस्त 2025 तक राजस्थान सीमा पर 'ऑपरेशन अलर्ट' शुरू किया।

भारत के स्वतंत्रता दिवस से पहले कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के तहत, सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) ने 11 से 17 अगस्त 2025 के बीच राजस्थान-पाकिस्तान सीमा पर 'ऑपरेशन अलर्ट' चलाया। इस अभियान का उद्देश्य घुसपैठ, तस्करी और अन्य सीमा पार खतरों को विफल करना था।

• BSF ने औपचारिक रूप से 11 अगस्त 2025 को ऑपरेशन अलर्ट शुरू किया, जिसे 17 अगस्त की मध्यरात्रि तक जारी रखने की योजना है। यह पहल स्वतंत्रता दिवस से पहले की सुरक्षा सतर्कता को दर्शाती है जिसका उद्देश्य सीमा पर स्थिरता सुनिश्चित करना और सीमा पार से आने वाले खतरों को रोकना है।

• ऑपरेशन का एक प्रमुख पहलू मानक संचालन प्रक्रियाओं (SOPs) और अभ्यासों की गहन समीक्षा और पूर्वाभ्यास था, जैसा कि BSF DIG (सेक्टर दक्षिण) एमके नेगी ने बताया। इसमें वास्तविक समय की खुफिया सूचनाओं का मूल्यांकन करना और सभी पोस्टिंगों में तैयारियों को बढ़ाना शामिल था।

Key Points:-

(i) BSF ने पैदल और ऊँट गश्त में उल्लेखनीय वृद्धि की, अतिरिक्त सुरक्षा चौकियाँ स्थापित कीं और चौबीसों घंटे निगरानी बनाए रखी। सीमा पर सतत निगरानी और रोकथाम सुनिश्चित करने के लिए संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त सैनिक तैनात किए गए।

(ii) ऑपरेशन अलर्ट का मुख्य उद्देश्य स्वतंत्रता दिवस के दौरान सीमा पार किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या अवैध गतिविधियों को रोकना था। सुरक्षा को सुदृढ़ करके, BSF का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि सीमा पर देशभक्ति की भावनाएँ निर्बाध और प्रबल बनी रहें।

(iii) जहाँ पारंपरिक गश्ती विधियों पर ज़ोर दिया जाता रहा, वहीं BSF ने खुफिया जानकारी इकट्ठा करने और उस पर प्रभावी ढंग से कार्रवाई करने के लिए उन्नत तकनीकों—जैसे उन्नत निगरानी उपकरणों—को भी शामिल किया। तकनीक-समर्थित निगरानी और पारंपरिक क्षेत्रीय रणनीति के इस मिश्रण ने संवेदनशील अवधि के दौरान सीमा पर लचीलेपन को मज़बूत करने में मदद की।

6. UPSC 1 अक्टूबर 2025 से वर्ष भर चलने वाला शताब्दी समारोह शुरू करेगा, जो 1926 में इसकी स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में होगा।

सिविल सेवा भर्ती के लिए भारत का प्रमुख संवैधानिक निकाय, संघ लोक सेवा आयोग (UPSC), 1 अक्टूबर 2025 से एक वर्ष तक चलने वाला शताब्दी समारोह

शुरू करेगा, जो 1926 में स्थापना के बाद से अपनी सेवा के सौवें वर्ष को चिह्नित करेगा। यह पहल आयोग की पारदर्शिता, योग्यता और सार्वजनिक विश्वास की विरासत को रेखांकित करती है।

• वर्ष भर चलने वाले इस समारोह में सेमिनार, व्याख्यान, प्रकाशन और UPSC की निष्पक्षता एवं सत्यनिष्ठा के मूल्यों को दर्शाने के लिए एक विशेष शताब्दी प्रतीक चिन्ह जैसे विविध स्मारक कार्यक्रम शामिल होंगे। योजनाओं में एक जन-पहुँच घटक भी शामिल है, जिसमें प्रख्यात सिविल सेवक और लोक प्रशासन विशेषज्ञ उम्मीदवारों और नागरिकों, दोनों के साथ अपने विचार साझा करेंगे।

• महत्व का विवरण देते हुए, अध्यक्ष ने UPSC की इस उपलब्धि को एक उत्सव से कहीं अधिक बताया - यह संवैधानिक मूल्यों, योग्यता आधारित चयन और सिविल सेवा नियुक्तियों में जनता के विश्वास को बनाए रखने की निरंतर प्रतिबद्धता का प्रतिनिधित्व करता है।

Key Points:-

(i) UPSC के शताब्दी समारोह में कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय सीधे तौर पर शामिल होगा, जिसके अधिकार क्षेत्र में आयोग कार्य करता है। कार्यक्रम नई दिल्ली के शाहजहाँ रोड स्थित धौलपुर हाउस स्थित यूपीएससी मुख्यालय में आयोजित किए जाएँगे, और भारत की सिविल सेवाओं के क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थानों में भी कार्यक्रम आयोजित किए जाएँगे।

(ii) भारतीय संविधान के भाग XIV के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय के रूप में स्थापित, UPSC अखिल भारतीय सेवाओं और केंद्रीय सिविल सेवाओं (समूह क और ख) में अधिकारियों की नियुक्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसकी शताब्दी ऐसे समय में मनाई जा रही है जब प्रतिवर्ष 13 लाख से अधिक आवेदक सीमित संख्या में सिविल सेवा पदों के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं।

(iii) यह महत्वपूर्ण वर्ष UPSC के विकास पर चिंतन को आमंत्रित करता है - 1926 के इसके प्रारंभिक वर्षों से लेकर प्रारंभिक, मुख्य परीक्षा और व्यक्तित्व परीक्षण तक आधुनिक परीक्षा संचालन तक - और निष्पक्षता और उत्कृष्टता के माध्यम से लोक प्रशासन और शासन को बढ़ाने के आयोग के संकल्प को मजबूत करता है।

INTERNATIONAL

1. नेपाल ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 97 हिमालयी चोटियों के लिए परमिट शुल्क माफ कर दिया।

नेपाल ने अपने सुदूर पश्चिमी क्षेत्रों - करनाली और सुदूरपश्चिम - में 97 हिमालयी चोटियों के लिए अगले दो वर्षों के लिए परमिट शुल्क माफ करने का साहसिक कदम उठाने की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य पर्वतारोहियों को कम खोजे गए क्षेत्रों की ओर आकर्षित करना और स्थानीय पर्यटन-संचालित अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ावा देना है।

• नेपाल के संस्कृति, पर्यटन और नागरिक उड्डयन मंत्रालय (MoTCA) के अंतर्गत आने वाले पर्यटन विभाग ने खुलासा किया है कि परमिट छूट कर्णाली और सुदूरपश्चिम प्रांतों में 5,870 मीटर से 7,132 मीटर तक की 97 चोटियों पर लागू होती है। 27 जुलाई 2025 को कैबिनेट की बैठक में स्वीकृत और

11 अगस्त को घोषित इस पहल का उद्देश्य देश के कुछ सबसे कम विकसित क्षेत्रों में पर्वतारोहण के नए आयाम खोलना है।

• यह नीति 2008 और 2018 के बीच जारी की गई इसी तरह की छूट जैसे पहले के नियंत्रित प्रयोगों पर आधारित है। पिछले दो वर्षों में, 21 टीमों के केवल 68 पर्वतारोहियों ने इनमें से केवल 15 चोटियों के लिए परमिट हासिल किया, जिससे रॉयल्टी के रूप में मात्र 1.4 मिलियन रुपये की कमाई हुई।

• इसके साथ ही, नेपाल ने माउंट एवरेस्ट के लिए परमिट शुल्क में नाटकीय वृद्धि की है - 11,000 अमेरिकी डॉलर से बढ़ाकर 15,000 अमेरिकी डॉलर प्रति पर्वतारोही, जो 1 सितंबर 2025 से प्रभावी होगा - यह भीड़भाड़ को कम करने और नाजुक पर्वत पारिस्थितिकी की रक्षा करने के प्रयासों का हिस्सा है।

Key Points:-

(i) अधिकारियों को उम्मीद है कि निःशुल्क परमिट की पहल से एवरेस्ट से हिमालय के पश्चिमी आंतरिक क्षेत्र में पर्वतारोहियों की आवाजाही कम हो जाएगी, जिससे गाइडों, पोर्टरों और आतिथ्य सेवाओं के लिए नौकरियां पैदा होंगी, साथ ही खराब सड़क नेटवर्क और सीमित सुविधाओं वाले क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा मिलेगा।

(ii) आर्थिक अवसरों को सुरक्षा और तैयारी के साथ संतुलित करने के लिए, नेपाल सरकार ऐसे नियमों पर भी विचार कर रही है जिनके तहत एवरेस्ट पर चढ़ने के इच्छुक लोगों को पहले नेपाल के भीतर 7,000 मीटर ऊँची चोटी पर चढ़ना अनिवार्य होगा। पर्यटन अधिनियम में यह संशोधन वर्तमान में संसद में विचाराधीन है।

(iii) दूरदराज के क्षेत्रों में चोटियों पर वित्तीय बाधाओं को दूर करके और प्रतिष्ठित शिखरों पर भीड़भाड़ को दूर करके, यह नीति नेपाल के हिमालय में टिकाऊ और न्यायसंगत पर्वतारोहण पर्यटन की दिशा में एक रणनीतिक बदलाव का प्रतिनिधित्व करती है।

BANKING & FINANCE

1. NABARD, APGB और एक्वा एक्सचेंज ने आंध्र प्रदेश में संपार्श्विक-मुक्त IoT-सक्षम झींगा पालन ऋण लॉन्च किया।

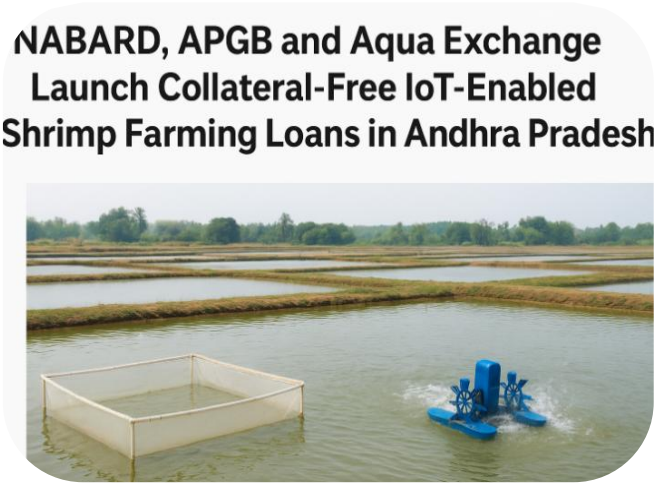

11 अगस्त, 2025 को, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD), आंध्र प्रदेश ग्रामीण बैंक (APGB) और एक्वा एक्सचेंज एग्रीटेक प्राइवेट लिमिटेड ने विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश में एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए, जिसका उद्देश्य झींगा किसानों का समर्थन करने और टिकाऊ जलीय कृषि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक पायलट इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT)-सक्षम संपार्श्विक-मुक्त ऋण मॉडल पेश करना है।

• संपार्श्विक-मुक्त झींगा पालन ऋण योजना कम ब्याज, बिना संपार्श्विक ऋण प्रदान करती है, किसानों को औपचारिक ऋण प्रणाली में एकीकृत करती है, अनौपचारिक उधारदाताओं पर निर्भरता कम करती है, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देती है, टिकाऊ जलीय कृषि का समर्थन करती है, और भारत के जलीय कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देते हुए आर्थिक स्थिरता को बढ़ाती है।

• इस पायलट कार्यक्रम के तहत, लगभग 100 झींगा किसानों को 3-6 महीनों के भीतर कुल 25 करोड़

रुपये के ज़मानत-मुक्त ऋण वितरित किए जाएँगे। पाँच चयनित किसानों को 1.25 करोड़ रुपये की प्रारंभिक किश्त स्वीकृत की जाएगी, जो कार्यक्रम के विस्तार के लिए एक मानक के रूप में काम करेगी। इस पहल का उद्देश्य जलीय कृषि में ऋण संबंधी निर्णयों में सहायता के लिए IoT-सक्षम निगरानी की व्यवहार्यता का प्रदर्शन करना है।

• इस कार्यक्रम के महत्वाकांक्षी विस्तार लक्ष्य हैं, जिनमें वित्तीय वर्ष 2025-26 (वित्त वर्ष 26) के दौरान 100 करोड़ रुपये और वित्त वर्ष 27 में 250 करोड़ रुपये के ऋण वितरित करने की योजना है। ये अनुमान सरकार और वित्तीय संस्थानों की झींगा किसानों को बड़े पैमाने पर औपचारिक वित्तपोषण संरचनाओं में एकीकृत करने की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं, साथ ही भारत के झींगा पालन उद्योग की उत्पादकता और स्थिरता को बढ़ावा देते हैं।

Key Points:-

(i) झींगा किसानों की ऋण-योग्यता का आकलन करने के लिए एक फार्म रेटिंग स्कोर (FRS) प्रणाली शुरू की जाएगी। यह FRS भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के एकीकृत ऋण इंटरफ़ेस (ULI) के अंतर्गत ऋणदाताओं के लिए एक मानक के रूप में कार्य करेगा। यह स्कोरिंग प्रणाली पारदर्शिता, मानकीकरण और जलीय कृषि उद्यमियों के लिए औपचारिक वित्त तक आसान पहुँच सुनिश्चित करती है, साथ ही ऋणदाता संस्थानों के लिए जोखिम भी कम करती है।

(ii) इस पहल में इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) तकनीक का इस्तेमाल किया गया है ताकि पानी की गुणवत्ता, चारे के इस्तेमाल और बीमारियों की रोकथाम जैसे प्रमुख मापदंडों की वास्तविक समय में निगरानी की जा सके। IoT उपकरणों का लाभ उठाकर, किसान झींगा उत्पादकता को बेहतर बना सकते हैं, पर्यावरणीय और जैविक जोखिमों से होने वाले नुकसान को कम कर सकते हैं और परिचालन दक्षता बढ़ा सकते हैं। यह तकनीक-आधारित दृष्टिकोण भारत के जलीय कृषि क्षेत्र के आधुनिकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

(iii) NABARD, APGB और एक्वा एक्सचेंज का सहयोग कृषि वित्तीय समावेशन को बढ़ाने वाली एक सार्वजनिक-निजी साझेदारी को दर्शाता है। नाबार्ड नीति और वित्त पोषण का मार्गदर्शन करता है, APGB जमीनी स्तर पर ऋण वितरण का प्रबंधन करता है, और एक्वा एक्सचेंज IoT सहायता प्रदान करता है, जिससे टिकाऊ जलीय कृषि, औपचारिक ऋण और ग्रामीण वित्त में प्रौद्योगिकी एकीकरण को बढ़ावा मिलता है।

2. RBL बैंक ने भारतीय उद्यमों को लक्षित करते हुए नया डिजिटल भुगतान गेटवे लॉन्च करने के लिए CAMSPay के साथ सहयोग किया।

12 अगस्त, 2025 को मुंबई, महाराष्ट्र में, RBL बैंक ने भारतीय उद्यमों की सेवा के उद्देश्य से एक नया डिजिटल भुगतान गेटवे प्लेटफॉर्म पेश करने के लिए कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज (CAMS) की भुगतान इकाई, कैम्सपे के साथ एक रणनीतिक साझेदारी की।

• RBL बैंक निपटान सेवा भागीदार के रूप में कार्य करेगा, जो विभिन्न उद्योगों में उच्च-मात्रा वाले लेनदेन के लिए सुचारू और कुशल निपटान सेवाएँ प्रदान करने हेतु अपने बैंकिंग बुनियादी ढाँचे का लाभ उठाएगा। इस साझेदारी का उद्देश्य भारत में

डिजिटल भुगतान प्रसंस्करण की गति, सुरक्षा और नियामक अनुपालन को बढ़ावा देना है।

• प्रौद्योगिकी प्रदाता के रूप में कार्य करते हुए, CAMSPay उन्नत भुगतान प्रौद्योगिकी सुविधाएँ प्रदान करेगा, जिनमें रीयल-टाइम निपटान क्षमताएँ, सुरक्षित कार्ड और बैंक-आधारित प्रसंस्करण, और स्वचालित समाधान शामिल हैं। यह प्लेटफ़ॉर्म खुले API के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे विभिन्न व्यावसायिक प्रणालियों के साथ एकीकरण संभव होगा।

• यह सहयोग, बड़े पैमाने पर लेन-देन करने वाले उद्यमों के लिए स्केलेबल, विनियमन-तैयार समाधान प्रदान करके उद्योग-व्यापी भुगतान चुनौतियों का समाधान करता है। यह तेज़ और विश्वसनीय भुगतान निपटान चक्रों को सक्षम करते हुए अनुपालन मानदंडों का पालन भी सुनिश्चित करता है।

Key Points:-

(i) इस साझेदारी में प्रमुख नेताओं में RBL बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) आर सुब्रमण्यकुमार और कैम्सपे के CEO वसंत जयपॉल शामिल हैं।

(ii) उनका संयुक्त दृष्टिकोण तकनीकी रूप से उन्नत, उद्यम-अनुकूल भुगतान गेटवे बनाने पर केंद्रित है जो भारतीय व्यवसायों की उभरती मांगों को पूरा करता है।

(iii) इस डिजिटल भुगतान गेटवे के शुभारंभ से भारत में उद्यमों के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, सुचारू लेनदेन का समर्थन करने, भुगतान में देरी को कम करने और व्यावसायिक भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र की समग्र दक्षता को बढ़ाने की उम्मीद है।

ECONOMY & BUSINESS

1. टाटा की नेल्को भारत में यूटेलसैट वनवेब LEO सैटेलाइट सेवाएँ शुरू करेगी।

अगस्त 2025 में, टाटा समूह की उपग्रह संचार कंपनी, नेल्को लिमिटेड ने भारत भर में वनवेब लो अर्थ ऑर्बिट (LEO) उपग्रह कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए फ्रांसीसी उपग्रह प्रदाता यूटेलसैट के साथ साझेदारी की, जिसका उद्देश्य डिजिटल बुनियादी ढांचे, कनेक्टिविटी और राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ाना है।

• यह सहयोग भारत के भूभाग, प्रादेशिक जल और दूरदराज के क्षेत्रों में सुरक्षित, उच्च गति और कम विलंबता वाला उपग्रह इंटरनेट प्रदान करेगा, जिससे सरकार, उद्यम और वंचित क्षेत्रों के लिए निरंतर कनेक्टिविटी सुनिश्चित होगी।

• LEO उपग्रह सेवाओं का लाभ उठाकर, यह पहल भारत के डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करती है और राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ाती है, तथा भूमि, समुद्र और वायु क्षेत्रों में महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए विश्वसनीय संचार प्रदान करती है।

Key Points:-

(i) LEO-आधारित कनेक्टिविटी कम विलंबता संचार, उच्च गति इंटरनेट और विश्वसनीय सेवाओं को सुनिश्चित करती है, यहां तक कि उन क्षेत्रों में भी जहां स्थलीय नेटवर्क सीमित या अनुपलब्ध हैं, तथा

डिजिटल विभाजन को पाटती है।

(ii) वनवेब, जिसे शुरू में भारती एंटरप्राइजेज द्वारा समर्थित किया गया था, का 2023 में यूटेलसैट के साथ विलय हो गया, जिससे यह 669 उपग्रहों के साथ दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह ऑपरेटर बन गया, जो अब भारत-केंद्रित तैनाती के लिए नेल्को के साथ सहयोग कर रहा है।

(iii) उपग्रह सेवाओं से सरकारी कार्यों, उद्यम संपर्क, रक्षा, आपदा प्रबंधन और दूरस्थ क्षेत्र संचार को समर्थन मिलने की उम्मीद है, जिससे पूरे भारत में आर्थिक विकास और तकनीकी उन्नति को बढ़ावा मिलेगा।

2. LTIMindtree ने अमरावती में भारत का पहला क्वांटम वैली टेक पार्क विकसित करने के लिए आंध्र प्रदेश के साथ साझेदारी की है।

11 अगस्त, 2025 को, सूचना प्रौद्योगिकी (IT) सेवा और परामर्श कंपनी LTIMindtree ने अपने मूल समूह लार्सन एंड टुब्रो (L&T) के साथ मिलकर आंध्र प्रदेश सरकार और उद्योग हितधारकों के साथ अमरावती, आंध्र प्रदेश में भारत का पहला क्वांटम वैली टेक पार्क स्थापित करने के लिए एक रणनीतिक सहयोग की घोषणा की।

• इस साझेदारी के तहत, LTIMindtree क्वांटम वैली में एक उत्कृष्टता केंद्र (CoE) स्थापित करेगा जो गहन तकनीकी अनुसंधान, क्वांटम शिक्षा, इनक्यूबेशन सहायता और अनुप्रयुक्त अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी) को बढ़ावा देगा। यह उत्कृष्टता केंद्र उभरती क्वांटम प्रौद्योगिकियों में नवाचार के केंद्र के रूप में कार्य करेगा।

• L&T क्वांटम वैली टेक पार्क के भौतिक बुनियादी ढांचे के डिजाइन, विकास और प्रबंधन का कार्यभार संभालेगी, और बड़े पैमाने पर प्रौद्योगिकी और निर्माण परियोजनाओं के क्रियान्वयन में अपनी विशेषज्ञता का उपयोग करेगी। इसमें अनुसंधान और औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं का निर्माण शामिल है।

Key Points:-

(i) इस पहल का एक प्रमुख आकर्षण क्वांटम कंप्यूटिंग केंद्र में IBM क्वांटम सिस्टम टू का एकीकरण है, जिसे इंटरनेशनल बिज़नेस मशीन्स (IBM) और आंध्र प्रदेश सरकार के सहयोग से विकसित किया गया है। यह इसे भारत का सबसे बड़ा क्वांटम कंप्यूटिंग परिनियोजन बना देगा।

(ii) यह साझेदारी LTIMindtree और L&T को क्वांटम वैली पारिस्थितिकी तंत्र में मुख्य प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे के नेताओं के रूप में स्थापित करती है, जिससे वैश्विक प्रतिभाओं को आकर्षित करने, अनुसंधान क्षमताओं को बढ़ावा देने और उन्नत क्वांटम कंप्यूटिंग प्रौद्योगिकियों में भारत की स्थिति को मजबूत करने की उम्मीद है।

(iii) सरकारी सहायता, कॉर्पोरेट विशेषज्ञता और वैश्विक प्रौद्योगिकी साझेदारी को एक साथ लाकर, क्वांटम वैली टेक पार्क का उद्देश्य वैश्विक क्वांटम अनुसंधान परिदृश्य में भारत की यात्रा को गति देना और अगली पीढ़ी के कंप्यूटिंग के लिए औद्योगिक अनुप्रयोगों को बढ़ावा देना है।

APPOINTMENTS & RESIGNATIONS

1. ओडिशा ने माधुरी दीक्षित को राज्य के हथकरघा उद्योग के लिए ब्रांड एंबेसडर नियुक्त किया।

अगस्त 2025 में, ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री और पद्म श्री पुरस्कार विजेता माधुरी दीक्षित को राज्य के हथकरघा उद्योग के लिए ब्रांड एंबेसडर नियुक्त करने की घोषणा की, जिसका उद्देश्य इसकी समृद्ध विरासत को बढ़ावा देना और स्थानीय कारीगरों को सशक्त बनाना है।

- **यह नियुक्ति टेक्सटाइल एडवांटेज (EKTA) कार्यक्रम के लिए प्रदर्शनी-सह-ज्ञान साझाकरण के उद्घाटन के दौरान घोषित की गई, जो 7 अगस्त, 2025 को जनता मैदान, भुवनेश्वर में 11वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह के साथ मेल खाता है।**

- **EKTA ओडिशा सरकार द्वारा हथकरघा कारीगरों को बेहतर बाजार पहुंच, कौशल प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता प्रदान करने का एक प्रमुख प्रयास है, जिससे पारंपरिक बुनाई प्रथाओं का सतत विकास और संरक्षण सुनिश्चित हो सके।**

Key Points:-

(i) ब्रांड एंबेसडर के रूप में, माधुरी दीक्षित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ओडिशा के हथकरघा उत्पादों को बढ़ावा देंगी, जिससे राज्य के कपड़ा उद्योग की शिल्प कौशल और सांस्कृतिक महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ेगी।

(ii) एक प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री, नृत्यांगना और समाजसेवी, माधुरी दीक्षित ने चार दशकों के करियर में 70 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया है, और एक सांस्कृतिक प्रतीक तथा सौंदर्य और कलात्मक उत्कृष्टता का प्रतीक बन गई हैं।

(iii) माधुरी दीक्षित को 2008 में 'कला' श्रेणी में पद्मश्री मिला और उन्हें 2023 में गोवा में आयोजित 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (IFFI) में भारतीय सिनेमा के लिए विशेष मान्यता पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

SPORTS

1. भारत ने एशियाई अंडर-19 और अंडर-22 मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में 27 पदक जीते।

अगस्त 2025 में बैंकॉक में आयोजित एशियाई अंडर-19 और अंडर-22 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत ने शानदार प्रदर्शन किया और दोनों आयु वर्गों में कुल 27 पदक हासिल किए - जो एशियाई युवा मुक्केबाजी में देश के बढ़ते प्रभुत्व को दर्शाता है।

- **भारत के 40 मुक्केबाजों के दल - प्रत्येक आयु वर्ग में 20 - ने 27 पदक जीते। अंडर-19 टीम ने 14 पदक (3 स्वर्ण, 7 रजत, 4 कांस्य) जीते और कुल मिलाकर दूसरे स्थान पर रही, जबकि अंडर-22 टीम ने 13**

पदक जीतकर महाद्वीपीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन किया।

• अंडर-19 वर्ग में, खासकर महिला मुक्केबाजों का प्रदर्शन शानदार रहा। निशा (54 किग्रा) और मुस्कान (57 किग्रा) ने अपने-अपने वर्गों में स्वर्ण पदक जीते, जबकि राहुल कुंडू ने पुरुषों के 75 किग्रा वर्ग के फाइनल में कड़ी मेहनत से स्वर्ण पदक जीता। शीर्ष स्तर की ये जीत युवा मुक्केबाजी में भारत की मजबूती को दर्शाती हैं।

Key Points:-

(i) अंडर-22 वर्ग में, कई मुक्केबाज़ों ने फ़ाइनल में जगह बनाई: नीरज (75 किग्रा), इशान कटारिया (90+ किग्रा), यात्री पटेल (57 किग्रा), और प्रिया (60 किग्रा), जिससे कम से कम रजत पदक पक्का हो गया। इसके अलावा, रितिका ने महिलाओं के 80+ किग्रा वर्ग में स्वर्ण पदक जीता, जिससे भारत ने 13 पदकों के साथ अपने अभियान का शानदार समापन किया।

(ii) इस चैंपियनशिप ने एशियाई युवा मुक्केबाजी में भारत की बढ़ती स्थिति की पुष्टि की। अंडर-19 और अंडर-22, दोनों स्तरों पर पदकों की झड़ी के साथ, ये परिणाम मज़बूत जमीनी स्तर पर किए गए प्रयासों को दर्शाते हैं—जमीनी प्रशिक्षण से लेकर भारतीय मुक्केबाजी महासंघ (BFI) द्वारा रणनीतिक निवेश तक—और अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारतीय मुक्केबाजी के उज्ज्वल भविष्य का संकेत देते हैं।

AWARDS

1. कर्नाटक की बीबी फातिमा महिला SHG ने जलवायु-लचीली खेती और जैव विविधता संरक्षण के लिए यूएनडीपी इक्केटर पुरस्कार 2025 जीता।

कर्नाटक की महिलाओं के नेतृत्व वाली पहल, बीबी फातिमा स्वयं सहायता समूह (SHG) ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) द्वारा प्रतिष्ठित इक्केटर पुरस्कार 2025 जीता है, जिसमें 30 गांवों में जलवायु-लचीली कृषि और जैव विविधता संरक्षण में इसके अनुकरणीय कार्य को मान्यता दी गई है।

• 8 अगस्त 2025 को एक विशेष आभासी समारोह में, विश्व के स्वदेशी लोगों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के साथ, UNDP ने इक्केटर पुरस्कार 2025 के 10 वैश्विक विजेताओं में बीबी फातिमा एसएचजी की घोषणा की। 103 देशों में फैली 700 से अधिक प्रविष्टियों में से चुने गए, समूह को उत्कृष्ट महिला और युवा-नेतृत्व वाले प्रकृति-आधारित समाधानों के लिए "जलवायु कार्रवाई के लिए प्रकृति" थीम के तहत मनाया गया है।

• कर्नाटक के धारवाड़ जिले के कुंडगोल तालुका के तीर्था गाँव में 2018 में स्थापित, यह स्वयं सहायता समूह सहज समृद्ध के मार्गदर्शन में मात्र 15 महिलाओं के साथ शुरू हुआ था। अब यह समूह बाजरा-आधारित मिश्रित फसल, जलवायु-अनुकूल खेती, पशुपालन और सामुदायिक बीज बैंकों जैसी नवीन पद्धतियों के माध्यम से 30 गाँवों के 5,000 किसानों को सहायता प्रदान करता है।

Key Points:-

(i) समूह का कार्य पारंपरिक ज्ञान को पुनर्योजी कृषि

और नवीकरणीय ऊर्जा के साथ एकीकृत करता है, जिससे जैव विविधता पुनर्स्थापन, पोषण और खाद्य सुरक्षा, और हाशिए पर पड़ी महिलाओं और युवाओं को कृषि-उद्यमियों के रूप में सशक्त बनाने में योगदान मिलता है। इन प्रयासों ने ग्रामीण आजीविका और पारिस्थितिक लचीलेपन को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ावा दिया है।

(ii) इस पुरस्कार में 10,000 अमेरिकी डॉलर (लगभग ₹8.5 लाख) का नकद पुरस्कार और अंतर्राष्ट्रीय मान्यता शामिल है। इस सम्मान से बीबी फ़ातिमा एसएचजी को अर्जेंटीना, ब्राज़ील, पेरू, इंडोनेशिया, केन्या, तंजानिया, पापुआ न्यू गिनी और इक्वाडोर के विजेताओं के साथ स्थान मिला है, जिससे इसकी वैश्विक प्रतिष्ठा और प्रभाव और भी मज़बूत हुआ है।

(iii) इस सम्मान को अक्सर "जैव विविधता के लिए नोबेल पुरस्कार" कहा जाता है, और यह जलवायु परिवर्तन से निपटने, टिकाऊ कृषि प्रणालियों को बढ़ावा देने और जैव विविधता को संरक्षित करने में जमीनी स्तर पर महिलाओं के नेतृत्व वाली सामुदायिक कार्रवाई की परिवर्तनकारी क्षमता को रेखांकित करता है।

IMPORTANT DAYS

1. संयुक्त राष्ट्र ने 11 अगस्त 2025 को विश्व स्टीलपैन दिवस गया।

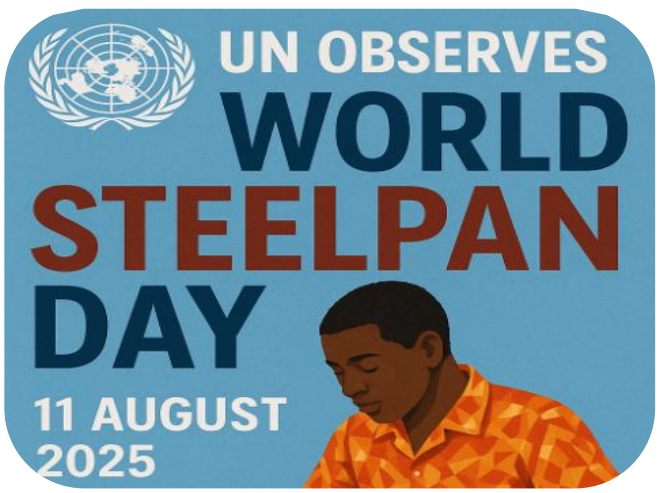

11 अगस्त 2025 को, संयुक्त राष्ट्र (UN) ने त्रिनिदाद और टोबैगो (T&T) के राष्ट्रीय संगीत वाद्ययंत्र, स्टीलपैन के सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और विकासात्मक महत्व पर प्रकाश डालते हुए, विश्व स्टीलपैन दिवस का तीसरा संस्करण मनाया। यह दिवस दुनिया भर में सांस्कृतिक विरासत और सतत विकास को बढ़ावा देने में इसकी भूमिका पर ज़ोर देता है।

- **विश्व स्टीलपैन दिवस औपचारिक रूप से 2022 में प्रस्तावित किया गया था जब त्रिनिदाद और टोबैगो (T&T) सरकार ने संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (UNESCO) से 11 अगस्त को वार्षिक उत्सव के रूप में घोषित करने का अनुरोध किया था। इसका उद्देश्य स्टीलपैन के वैश्विक सांस्कृतिक प्रभाव को मान्यता देना और आने वाली पीढ़ियों के लिए इसकी विरासत को संरक्षित करना था।**

- **24 जुलाई 2023 को, संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) ने प्रस्ताव A/RES/77/316 को अपनाया, जिसके तहत आधिकारिक तौर पर हर साल 11 अगस्त को विश्व स्टीलपैन दिवस घोषित किया गया। इस प्रस्ताव में संगीत, सांस्कृतिक पहचान और सतत विकास में स्टीलपैन के अद्वितीय योगदान को मान्यता दी गई।**

- **पहली बार विश्व स्टीलपैन दिवस 11 अगस्त 2023 को विश्व स्तर पर मनाया गया। इसमें सांस्कृतिक प्रदर्शन, शैक्षिक गतिविधियाँ और जागरूकता अभियान शामिल थे, जो कैरेबियन क्षेत्र से परे वाद्ययंत्र के इतिहास और प्रभाव को प्रदर्शित करते थे।**

Key Points:-

(i) 11 अगस्त को आयोजित 2025 के समारोह का विषय था, "जड़ों से प्रतिध्वनि तक: पीढ़ियों और राष्ट्रों में प्रतिध्वनि।" इसमें संगीत की सराहना में पीढ़ियों के बीच के अंतर को पाटने, सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देने और एकता को बढ़ावा देने में स्टीलपैन

की भूमिका पर ज़ोर दिया गया।

(ii) 1992 से, पोर्ट ऑफ स्पेन (POS) स्थित पैन ट्रिनबागो इंक. टी.सी., हर अगस्त में "पैन मंथ" मनाता आ रहा है। यह वार्षिक आयोजन स्टीलपैन को टी.एंड.टी. के राष्ट्रीय संगीत वाद्ययंत्र के रूप में आधिकारिक रूप से घोषित किए जाने के उपलक्ष्य में आयोजित किया जाता है, जिसमें संगीत कार्यक्रम, परेड और शैक्षिक आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

(iii) 20वीं सदी में T&T में आविष्कृत स्टीलपैन को न केवल एक संगीतमय नवाचार के रूप में, बल्कि लचीलेपन और सांस्कृतिक गौरव के प्रतीक के रूप में भी मनाया जाता है। विश्व स्टीलपैन दिवस के माध्यम से, संयुक्त राष्ट्र सांस्कृतिक विविधता, युवा जुड़ाव और वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देकर संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों (SDG) में योगदान देने की अपनी क्षमता को रेखांकित करता है।

2. संयुक्त राष्ट्र ने 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2025 के रूप में मनाया।

संयुक्त राष्ट्र (UN) समाज में युवाओं की भूमिका का जश्न मनाने और उन्हें प्रभावित करने वाले मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस (IYD) मनाता है। यह दिवस जीवन के सभी क्षेत्रों में उनकी सक्रिय और समान भागीदारी को बढ़ावा देता है।

• 2025 का अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस विशेष महत्व रखता है क्योंकि यह सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) के लिए 2030 एजेंडा को अपनाने के एक दशक बाद का दिन है और युवाओं के लिए विश्व कार्य कार्यक्रम (WPAY) की 30वीं वर्षगांठ का स्मरण कराता है, जो युवा सशक्तिकरण नीतियों का मार्गदर्शन करने वाला एक वैश्विक ढांचा है।

• अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2025 का आधिकारिक विषय "सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) और उससे आगे के लिए स्थानीय युवा कार्य" है, जो वैश्विक विकास उद्देश्यों को प्राप्त करने में योगदान देने वाले जमीनी स्तर के युवा-नेतृत्व वाली पहलों पर केंद्रित है।

• अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की अवधारणा पहली बार 1991 में ऑस्ट्रिया के वियना में संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के विश्व युवा मंच के उद्घाटन सत्र के दौरान युवाओं के मुद्दों और योगदान को उजागर करने के लिए एक समर्पित वैश्विक दिवस के रूप में प्रस्तावित की गई थी।

Key Points:-

(i) 1998 में, युवाओं के लिए ज़िम्मेदार मंत्रियों के विश्व सम्मेलन (WCMRY) के पहले सत्र में 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस घोषित करने का प्रस्ताव पारित किया गया। अगले वर्ष, संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) ने अपने 54वें सत्र में, "युवाओं से जुड़ी नीतियाँ और कार्यक्रम" शीर्षक से प्रस्ताव A/RES/54/120 के माध्यम से इसका समर्थन किया।

(ii) पहला अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त 2000 को मनाया गया, जिसने वार्षिक वैश्विक समारोहों के लिए मंच तैयार किया जो सतत विकास, सामाजिक प्रगति और सांस्कृतिक उन्नति में युवाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करते हैं।

Static GK

Zepto Private Limited (Zepto)	CEO : आदित पालिचा	मुख्यालय : बेंगलुरु, कर्नाटक
Punjab	राजधानी: चंडीगढ़	मुख्यमंत्री: भगवंत मान
Zambia	राजधानी: लुसाका	मुद्रा: जाम्बियन क्वाचा
Andhra Pradesh	मुख्यमंत्री: एन. चंद्रबाबू नायडू	राज्यपाल: सैयद अब्दुल नज़ीर
Nelco Ltd	CEO : पी. जे. नाथ	स्थापना: 1940
Odisha	मुख्यमंत्री: मोहन चरण माझी	राज्यपाल: हरि बाबू कंभमपति
Karnataka	मुख्यमंत्री: सिद्धारमैया	राज्यपाल: थावर चंद गहलोत
Trinidad and Tobago (T&T)	प्रधान मंत्री (PM) कमला प्रसाद-बिसेस्सर	राजधानी: पोर्ट ऑफ स्पेन (PoS)
Nepal	राजधानी: काठमांडू	मुद्रा: नेपाली रुपया